

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या-218/2024

अन्तर्गत

अपील संख्या-2207/2023

लोकेश गुप्ता

—प्रार्थी—अपीलार्थी

बनाम

1. श्री प्रवीण गुप्ता, अति. मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. श्री के. के. पाठक, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. श्री डी.आर. मेघवाल, मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैकब रोड़, सिविल लाईन्स, जयपुर, राजस्थान।

—अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.11.2024

उपस्थित :-

प्रार्थी—अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता

अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री आकाश सोनी, विभागीय प्रतिनिधि

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी—अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 2277/2023 में दिनांक 22.09.2023 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 22.09.2023 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :-

"The present set of appeals are, therefore, allowed. Order dated 25.08.23 passed by Respondent Department is set-aside. The Respondent Department is directed to count the service/experience of the appellants on post of Assistant Engineer from 1.4.2008 for the purpose of promotion to the post of Executive Engineer (Civil)."

2. उनका आगे अभिकथन है कि अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 22.09.2023 के विरुद्ध प्रत्यर्थी विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 17604/2023, 17623/2023, 17624/2023, 17627/2023,

17628/2023, 17629/2023, 17632/2023, एवं 17633/2023 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आदेश दिनांक 30.08.2024 के द्वारा निर्णय पारित कर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं को खारिज किया है एवं अधिकरण के आदेश की पुष्टि की है, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिकरण के आदेश की पालना नहीं की है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 22.09.2023 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 22.09.2023 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा खण्डपीठ में विशेष याचिका प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निर्णय होना शेष है।
4. हमने अपीलार्थी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। हम पाते हैं कि अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की पालना अभी तक नहीं की गयी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस अधिकरण के आदेश की पुष्टि की है, उसके उपरान्त भी अभी तक आदेश की पालना न किया जाकर अधिकरण के आदेश की अवमानना की जा रही है। अधिकरण का आदेश पारित हुए करीब एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अधिकरण के आदेश की पालना नहीं की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के आदेश के संबंध में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश की पालना न कर लगातार अवमानना की जा रही है।
5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2023 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :-

"The present set of appeals are, therefore, allowed. Order dated 25.08.23 passed by Respondent Department is set-aside. The Respondent Department is directed to count the service/experience of

the appellants on post of Assistant Engineer from 1.4.2008 for the purpose of promotion to the post of Executive Engineer (Civil)."

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिस्थीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी काउंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the

preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 22.09.2023 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।
10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी-अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)